

लय ने कक्षों में घुसकर वकीलों, कर्मचारियों और जन-साधारण को लाठियों से पीटा और दर्जनों व्यक्तियों को घायल कर दिया। गत 4 फरवरी, 1983 को आजमगढ़ जिला अधिवक्ता संघ और दीवानी अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक हुई, जिसको उस दिन मैंने भी संबोधित किया था और उस बैठक में प्रदेश वार कौंसिल के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि और अन्य अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बैठक की कार्यवाही चल ही रही थी कि उस दिन पुनः पुलिस ने लाठी चार्ज किया और न्यायालय के परिसर में घुसकर मारपीट की। पुलिस की इस प्रकार बर्बरता से पूरे उत्तर प्रदेश में रोष का वातावरण व्याप्त हो गया और पूरे प्रदेश के वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया और अपने रोष को प्रकट किया। आजमगढ़ के अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पास करके इस घटना के लिए जिम्मेदार अग्रणी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। उनकी यह मांग अत्यन्त उचित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस संबंध में कुछ कार्यवाही की है किन्तु वह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी. ए. सी. ने बहुत अधिक अनुशासनहीनता और जन-विरोधी रवैये का परिचय दिया है।

इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूँ कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी. ए. सी. संगठनों को इस प्रकार से पुनर्गठित करने के आदेश दें, जिससे वह संगठन जन-सेवा और समाज में शान्ति व्यवस्था बनाने का प्रहरी बन सके।

(vi) Need for proper development of medical science and technology

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): Mr. Deputy-Speaker, Sir, ever since 1947, our Prime Ministers have evinced keen interest in the progress of science and technology in India and have themselves taken charge of the portfolios of science and technology. Unfortunately, in this grouping, the medical science and technology did not find place. It was left to the care of the Ministry of Health, which is already overloaded with enormous problems and has little time or resources to encourage the growth of medical science and technology in our vast country. Agriculture and atomic energy have flourished due to the special encouragement given by the Prime Minister and the Ministers concerned. The present situation is that medical science and technology have not got the adequate attention from the Government of India as well as from the State Governments in our country, to allot sufficient funds and create the requisite organisation for the advancement of medical science and technology in a big way. If this is done, we need not depend on the western countries for combating various diseases, formulating new drugs to suit our country and people. May I, therefore, request the hon. Prime Minister of India, and the hon. Minister for Health to ponder over this vital issue and initiate some clear cut policy and methods by which medical science and technology in our country will receive as much encouragement as received by the other departments of science and technology, viz., agriculture, atomic energy, engineering, space etc.

I also request that this development of medical science and technology be looked after by our hon. Prime Minister herself, so that it could receive the requisite attention to make up the loss sustained so far, since independence in this field of medical science and technology.